Drishti IAS

करेंट अफेयर्स बिहार

अप्रैल (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

बिहार **3**

- बिहार में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिये विकसित होगा खेल परिसर 3
- बिहार में बन रहा देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल 3
- सीएससी की तरह विकसित किये जाएंगे बिहार के 8463 पैक्स 4
- जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बिहार के 4 ज़िले शीर्ष 10 में 5
- पश्चिमी चंपारण के सुगंधित मर्चा चावल को मिला जीआई टैग 5
- सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को मिला पद्म श्री पुरस्कार 6
- मुख्यमंत्री ने किया मुजफ्फरपुर में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 6
- बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 7
- बिहार को केंद्रीय कोटे से मिलने लगेगी करीब 9000 मेगावाट बिजली 7
- 'कोसी बेसिन विकास परियोजना' के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सड़क और पुल का होगा निर्माण 8
- शिक्षा के क्षेत्र में देश के टॉप पाँच ज़िलों में शेखपुरा पहले और पूर्णिया दूसरे स्थान पर 9
- बिहार में जाति गणना के दूसरे चरण का शुभारंभ 9
- बिहार की अंजनी ने भाला फेंक में जीता स्वर्ण 10
- दरभंगा में बनेगा बिहार का दूसरा एम्स, कैबिनेट ने तीन अरब से अधिक राशि की प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दी 10
- बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को मिलेगा जीआई टैग 10
- बिहार में 454 किलोमीटर फोर लेन को केंद्र की मंजूरी 11
- आईआईटी पटना और रॉइनेट सोल्यूशन के बीच हुआ एमओयू 12

नोट :

बिहार

बिहार में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिये विकसित होगा खेल परिसर

चर्चा में क्यों ?

30 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में 'आओ खेलो-सह-गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना'के तहत सभी ज़िला मुख्यालय में आउटडोर खेल परिसर यानी स्टेडियम विकसित किये जा रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- 'आओ खेलो-सह-गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना'के तहत 14 खेलों में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें एथलेटिक, वॉलीबाल, कबड्डी, खो-खो, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, फुटबाल, फेंसिंग, सेपक टेकरा, शतरंज, बॉस्केटबॉल, तीरंदाजी और योग की खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
- इन स्टेडियम में स्टेट लेवल तक के खेलों का आयोजन किया जाएगा। खिलाड़ियों को खेलने के लिये पटना या अन्य राज्यों में आने-जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
- पटना के कंकड़बाग में स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर के तर्ज पर सभी ज़िला मुख्यालयों के आउटडोर स्टेडियम को विकसित करने की योजना कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने बनाई है। इसमें मुख्य रूप से तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध प्रमंडल में आउटडोर स्टेडियम विकसित किये जाएंगे।
- राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिये प्रशिक्षण पर ज़ोर दिया जा रहा है। सरकार की योजना है कि अगर ज़रूरत पड़े, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच की सेवा भी ली जा सकती है।
- उल्लेखनीय है कि योजना के तहत राज्य के सभी 534 प्रखंडों में स्टेडियम के निर्माण की योजना है। इस योजना के तहत 312 प्रखंडों में निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसमें 221 प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण हो चुका है। शेष 222 प्रखंडों में से 27 प्रखंडों में वर्ष 2022-23 में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इस 27 में से चार प्रखंडों में 400 मीटर और बाकी 23 में 200 मी. ट्रैक युक्त स्टेडियम के निर्माण किये जाएगे।

बिहार में बन रहा देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल

चर्चा में क्यों ?

2 अप्रैल, 2023 को बिहार पथ विकास निगम के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 22.76 किलोमीटर है।

प्रमुख बिंदु

- इस पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर व पुल के दोनों तरफ एप्रोच रोड की लंबाई 13 किलोमीटर है। इस पुल के तैयार होने से दक्षिण बिहार व पड़ोसी राज्य झारखंड की तरफ से आने-जाने वाले वाहनों को उत्तर बिहार जाने के लिये पटना शहर में आने की ज़रूरत नहीं होगी, इससे शहर में वाहनों का दबाव कम होगा।
- लगभग 4988 करोड़ रुपए की कुल लागत वाले इस पुल का पटना छोर एनएच-30 पर सबलपुर में तथा वैशाली छोर एनएच-103 पर चकसिकंदर में है।
- गंगा पर सिक्स लेन एक्स्ट्रा डोज केबल पुल के बनने से राघोपुर दियारा की सूरत बदलने के साथ उत्तर बिहार के लिये नयी कनेक्टिविटी होगी।

नोट :

- सिक्स लेन पुल के निर्माण में गंगा में दो पिलर के बीच 160 मीटर की दूरी है। गंगा में मालवाहक जहाज़ों के आवागमन को देखते हुए यह दूरी रखी गई है। सिक्सलेन पुल में पटना दक्षिण छोड़ की तरफ से नदी में लगभग 1.5 किलोमीटर व बिदुपुर उत्तरी छोर से नदी में लगभग 8.5 किलोमीटर पुल बन रहा है।
- इस पुल का निर्माण गंगा के जलस्तर से 22 मीटर ऊँचाई पर हो रहा है। ताकि गंगा के अधिकतम जलस्तर से 12 से 13 मीटर के करीब ऊँचा होने से पुल पर जलस्तर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
- आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सिक्सलेन पुल से राघोपुर दियारा को जोड़ने के लिये लिंक रोड का निर्माण भी शुरू हो चुका है।

सीएससी की तरह विकसित किये जाएंगे बिहार के 8463 पैक्स

चर्चा में क्यों ?

3 अप्रैल, 2023 को बिहार के सहकारिता विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के सभी 8,463 पैक्सों (प्राथमिक कृषि साख समिति) को अब सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के रूप में विकसित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- सहकारिता विभाग के मुताबिक, बिहार के किसान अब पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समिति) में ई-केवाईसी करा सकेंगे। यह सुविधा कंप्यूटरीकृत किये जा रहे सभी 8,463 पैक्स में मिलेगी।
- पैक्सों के सामान्य सेवा केंद्रों के रूप में विकसित होने से 300 से अधिक सेवाएँ ग्रामीणों को मिल सकेंगी। किसान और अन्य ग्रामीण जल्द ही पैक्स के माध्यम से बैंकिंग, पीएम किसान ई-केवाईसी जैसी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- पैक्स को सामान्य सेवा केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को प्रदान करने के लिये सक्षम बनाए जाने हेतु सरकार की ओर से ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पहल से पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर योजना के डिजिटल सेवा पोर्टल पर सूचीबद्ध सभी सेवाएँ नागरिकों को प्रदान करने में सक्षम होगी।
- पैक्सों में ई-गवर्नेंस से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन का लक्ष्य रखा गया है, इसलिये सरकार ने पैक्स का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है तथा पैक्स से और अधिक किसानों को जोड़ा जाएगा।
- पैक्सों के माध्यम से अब बैंकिंग, इंश्योरेंस आधार, नामांकन, अपडेट, कानूनी सेवाएँ, कृषि इनपुट जैसे कृषि उपकरण,पैन कार्ड और आईआरसीटीसी, रेल, बस व विमान टिकट संबंधी सेवाएँ भी नागरिकों को प्रदान किया जाएगा।

नोट :

- इसके अलावा, पैक्स जल वितरण, भंडारण, बैंक मित्र सहित अलग-अलग गतिविधियाँ भी चला सकेंगे। पैक्स की व्यवसायिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और उन्हें आत्मनिर्भर आर्थिक संस्था बनने में भी मदद मिलेगी।
- उल्लेखनीय है कि सहकारिता के क्षेत्र में उठाया गया ये ऐतिहासिक कदम है। सहकारिता विभाग अभी से ग्रामीण अंचलों के लोगों और किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का काम कर रही है।

जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बिहार के 4 ज़िले शीर्ष 10 में

चर्चा में क्यों ?

4 अप्रैल, 2023 को केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिये जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के समस्तीपुर ज़िले को देशभर में पहला स्थान मिला है, वहीं इस सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर बिहार के शेखपुरा, तीसरे पर सुपौल और चौथे पायदान पर बांका ज़िला है।

प्रमुख बिंदु

- ज्ञातव्य है कि ज़िला स्तर पर यह कार्य मुख्य रूप से पीएचईडी एवं पंचायत राज विभाग के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। वहीं, चार अन्य ज़िलों की रैंकिंग को केंद्र सरकार ने वन टू टेन में रखा है। जहाँ हर घर नल का जल योजना का काम सबसे तेजी से हो रहा है।
- राज्य में स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर केंद्र ने भी हर माह जलापूर्ति सर्वेक्षण शुरू किया है। इसमें पानी की शुद्धता के बारे में लाभुकों से फीडबैक लिया जा रहा है। इसके जरिये केंद्र सरकार देश के सभी गाँवों में पेयजल की स्थिति का आकलन कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा ज़िला व राज्य की रैंकिंग मासिक और वार्षिक रूप से जारी होती है, इस सर्वेक्षण में बिहार के पाँच ज़िले सबसे ऊपर हैं।
- यह सर्वेक्षण मुख्यत: चार बिंदुओं पर किया गया था, इसमें ग्रामीण परिवारों के घरों में नल का जल की उपलब्धता, नल से मिलने वाले जल की मात्रा, जल की गुणवत्ता, जलापूर्ति की निरंतरता और पेयजल से संबंधित शिकायतों के मानकों पर ही संपादित किया गया।
- केंद्र सरकार के डैसबोर्ड पर सभी राज्यों के डेटा को देखा जाएगा। वहीं, बिहार में नल का जल किस तरह से काम कर रहा है, इसको लेकर दूसरे राज्यों को जानकारी दी जाएगी कि बिहार ने किस तरह से जलापूर्ति योजना में काम किया है।
- सर्वेक्षण शुरू होने से पूर्व सभी राज्यों की मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि यहाँ किये गए कार्यों को दूसरे उन राज्य में मॉडल रूप में प्रयोग किया जाएगा। जहाँ अभी तक कम से कम काम हुए हैं।
- इस सर्वेक्षण में टॉप टेन की रैंकिंग-
  - समस्तीपुर (बिहार)
  - शेखपुरा (बिहार)
  - सुपौल (बिहार)
  - बांका (बिहार)
  - वेल्लोर (तमिलनाडु)
  - सिरमौर (हिमाचल प्रदेश)
  - देहरादून (उत्तराखंड)
  - अन्नामबया (आंध्र प्रदेश)
  - लखीसराय (बिहार)
  - बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

पश्चिमी चंपारण के सुगंधित मर्चा चावल को मिला जीआई टैग

चर्चा में क्यों ?

4 अप्रैल, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के पश्चिमी चंपारण ज़िले के सुगंधित मर्चा/ मेरचा धान को ज्योग्रॉफिकल इंडीकेशन (जीआई) टैग प्राप्त हुआ है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि धान की इस स्वदेशी किस्म का उत्पादन केवल बिहार के पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में ही होती है। यह जानकारी जीआई जर्नल में प्रकाशित की गयी है।
- जीआई टैग के लिये आवेदन करने वाले मर्चा धान उत्पादक प्रगतिशील समूह को अब केवल औपचारिक तौर पर जीआई टैग का प्रमाण-पत्र मिलना बाकी रह गया है। प्रमाण-पत्र अगस्त में मिलेगा।
- मर्चा/ मेरचा धान की इस विशेष किस्म का आकार काली मिर्च से मिलता-जुलता होता है। यह धान बेहद सुगंधित और स्वादिष्ट होता है। इससे बनने वाला सुगंधित चूड़े की देश में ख्याति है।
- इसके उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी चंपारण ज़िले के मैनाटांड़, गौनाहा, नरकटियागंज, रामनगर, चनपटिया ब्लॉक है। इसकी औसत उपज 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस धान का पौधा लंबा होता है। इसकी उपज 145-150 दिन में तैयार हो जाती है। इस तरह पश्चिमी चंपारण के 18 ब्लॉक में से छह ब्लॉक में इसकी खेती की जाती है।
- उल्लेखनीय है कि इससे पहले बिहार के कृषि एवं उद्यानिकी के उत्पादों- जर्दालू आम, भागलपुर का कतरनी चावल, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, मगध क्षेत्र का मगही पान और मिथिला का मखाना को जीआई टैग मिल चुका है।
- इसके अलावा हस्तशिल्प में मंजूषा कला, सुजनी कढ़ाई का काम, एप्लिक खटवा वर्क, सिक्की घास के उत्पाद, भागलपुरी सिल्क, मधुबनी पेंटिंग और सिलाव के खाजा को भी जीआई टैग हासिल हो चुका है।
- जीआई टैग मिलने से संबंधित उत्पाद की पहचान वैश्विक फलक पर पहचानी जाती है। निर्यात को बढ़ावा मिलता है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलता है। जीआई टैग मिलने से उत्पाद को सुरक्षा और उसके संरक्षण की दिशा में सरकार किसानों का सहयोग करती है तथा एग्रो टूरिज्म भी बढ़ता है।

सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को मिला पद्म श्री पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

5 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार (द्वितीय संस्करण) में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के प्रसिद्ध संस्थान सुपर-30 के संचालक आनंद कुमार को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि आनंद कुमार प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिये प्रसिद्ध संस्थान सुपर-30 के संचालक हैं। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करने के लिये यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। इस साल कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री सम्मान शामिल हैं।
- इस अवसर पर आनंद कुमार ने कहा कि पद्म पुरस्कार मिलने के बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ी है। दूसरे राज्यों के छात्रों को शामिल करने के लिये सुपर 30 कार्यक्रम का और विस्तार करना चाहते हैं और इस साल के आखिर तक ऑनलाइन शिक्षा भी शुरू करना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री ने किया मुजफ्फरपुर में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

6 अप्रैल, 2023 को बिहार उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दक्षिण बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के मोतीपुर में ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया, जो 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने बताया है कि मोतीपुर में नये इथेनॉल प्लांट में 1,300 लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसमें 300 प्रत्यक्ष रूप से और 1,000 अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे।

नोट :

- विदित है कि एक वर्ष के अंदर यह दूसरा इथेनॉल प्लांट है, जिसका उद्घाटन हुआ है।
- उद्योग विभाग की ओर से बताया गया है कि बिहार भारत का अनाज आधारित इथेनॉल हब बनने की राह पर है। इसमें निकट भविष्य में उत्तर बिहार की अहम भूमिका होगी।
- सरकार की इथेनॉल नीति के तहत बिहार में कई और ग्रीन फील्ड प्लांट पूरा होने के करीब हैं। इसमें मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 3, बेगूसराय में 1 और बक्सर में 1 इथेनॉल प्लांट जून, 2023 तक पूरा होने की संभावना जतायी गई है।
- विभागीय आँकड़ों के अनुसार, मोतीपुर स्थित इथेनॉल प्लांट से प्रतिवर्ष 10 करोड़ लीटर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पूरे प्लांट में 320 केएलपीडी (किलो लीटर पर डे) की संयुक्त क्षमता की मशीनों को लगाया गया है। एक साथ चार इथेनॉल प्लांट के शुरू होने के बाद यह आँकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
- इस प्लांट के लगने से रोज़गार के साथ किसानों को भी इससे काफी लाभ होगा। इथेनॉल प्लांट में हर दिन सैकड़ों टन में मक्का या टूटे चावल की ज़रूरत होगी। इसकी खरीद के लिये किसानों से कंपनी सीधा संपर्क करेगी।
- ज्ञातव्य है कि मुजफ्फरपुर जिले में बड़े पैमाने पर मक्का की खेती होती है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर मक्के की मांग होने से किसानों को अच्छी कीमत मिल सकेगी। ज्यादातर बिचौलियों के कारण मक्का का उचित दाम नहीं मिल पाता है। वहीं पॉल्ट्री फीड प्लांट के लिये भी डीडीजी की उपलब्धता होगी।

बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023

चर्चा में क्यों ?

10 अप्रैल, 2023 को बिहार कैबिनेट ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 को स्वीकृति दी। इसके साथ ही पुराने ढर्रे पर नियुक्तियाँ कर रही इकाइयाँ भंग कर दी गई हैं।

प्रमुख बिंदु

- बिहार राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। सातवें फेज की होने वाली नियुक्तियों से यह नियमावली प्रभावी होगी। अब शिक्षक राज्य कर्मी कहलाएंगे।
- नई नियमावली के तहत CTET और STET पास अभ्यर्थियों को सीधे शिक्षक बनने का मौका मिलेगा और वह राज्यकर्मी बन जाएंगे। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनने के लिये प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा।
- नियोजित शिक्षकों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने शिक्षक बहाली के लिये न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कर दी है। अब आयोजन के जरिये शिक्षकों की बहाली की जाएगी।
- इसके अलावा मंत्रिमंडल ने महँगाई भत्ता बढ़ाने के एजेंडे पर भी मुहर लगा दी है। राज्यकर्मियों का महँगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाकर 38% से 42% कर दिया गया है। यह 1 जनवरी, 2023 से लागू हो जाएगा। एक जनवरी 2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता (DA) का लाभ मिलेगा। राज्य के कर्मचारियों के साथ पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
- बिहार कैबिनेट ने बिहार आकस्मिकता निधि को 300 करोड़ से बढ़ाकर इस वित्तीय वर्ष के लिये 10 हज़ार करोड़ रुपए अस्थायी रूप से करने की स्वीकृति भी दी है।

बिहार को केंद्रीय कोटे से मिलने लगेगी करीब 9000 मेगावाट बिजली

चर्चा में क्यों ?

11 अप्रैल, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार को 2024 तक केंद्रीय कोटे से करीब 9000 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- ज्ञातव्य है कि वर्तमान में एनटीपीसी की विभिन्न इकाइयों से बिहार राज्य को 6560 मेगावाट बिजली का आवंटन मिल रहा है।
- राज्य की बिजली कंपनियों ने अगले एक से डेढ़ वर्षों में एनटीपीसी बाढ़ की दो यूनिट, झारखंड के नॉर्थ कर्णपुरा की एक यूनिट और बक्सर की दो थर्मल पावर यूनिटों से करीब 1998 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आवंटन का अनुमान लगाया है।
- इसके अलावा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा ब्रेडा की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से भी करीब 760 मेगावाट बिजली मिलने का अनुमान है। ऐसे में बिहार को मिलने वाली बिजली की उपलब्धता 9000 मेगावाट को पार कर सकती है।
- एनटीपीसी के बाढ़ थर्मल पावर प्लांट में अब फेज वन की दो यूनिटों का चालू होना बाकी है। ऐसी संभावना है कि मई 2023 से 660 मेगावाट की फेज वन की दूसरी यूनिट से बिहार को 405 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने लगेगी। साथ ही, अप्रैल 2024 तक फेज वन की तीसरी व अंतिम यूनिट से भी 342 मेगावाट बिजली का कोटा उपलब्ध हो जाएगा।
- जानकारी के अनुसार झारखंड में स्थित नॉर्थ कर्णपुरा की दूसरी यूनिट भी जुलाई 2023 तक पूरी हो जाएगी। इसमें बिहार का कोटा 229 मेगावाट का है।
- बिजली कंपनियों ने 2024 तक बक्सर थर्मल पावर प्लांट की दोनों यूनिटों के चालू होने की उम्मीद जतायी है। हालाँकि वर्तमान में ज़मीन अधिग्रहण की समस्या को देखते हुए फिलहाल इसकी उम्मीद कम लग रही है।
- नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर बिजली कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) से विंड एनर्जी को लेकर 300 मेगावाट का समझौता किया है। यह बिजली दिसंबर 2023 तक उपलब्ध होगी। साथ ही, एसईसीआई के 230 मेगावाट के हाइब्रिड प्रोजेक्ट से भी दिसंबर 2023 तक जबकि ब्रेडा के सोलर पावर प्रोजेक्ट से मार्च 2024 तक 250 मेगावाट बिजली मिलने की उम्मीद जतायी गई है।
- वर्तमान में बिहार को एनटीपीसी की सिर्फ बाढ़ थर्मल पावर की तीन की इकाइयों से 1603 मेगावाट बिजली मिल रही है। इनमें स्टेज-2 की दो इकाइयों से 1,198 मेगावाट एवं स्टेज वन की एक इकाई से 405 मेगावाट बिजली शामिल है। स्टेज वन की दूसरी, तीसरी व अंतिम इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने पर इससे 810 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इससे बाढ़ प्लांट से मिलने वाली बिजली 1603 मेगावाट से बढ़कर 2000 मेगावाट से कुछ ज्यादा हो जाएगी।

'कोसी बेसिन विकास परियोजना' के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सड़क और पुल का होगा निर्माण

चर्चा में क्यों ?

11 अप्रैल, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोसी के बाढ़ प्रभावित लोगों के जीवन स्तर को सुदृढ़ बनाने के लिये 277 करोड़ रुपए की राशि से 'कोसी बेसिन विकास परियोजना' के तहत सड़क और पुल-पुलिया का निर्माण किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- ज्ञातव्य है कि विश्व बैंक संपोषित कोसी पुनर्वास योजना के दूसरे चरण का कार्य मार्च 2023 में पूरा होना था। लेकिन 72% ही काम अभी तक हुआ है, जिस कारण से कोसी पुनर्वास योजना के दूसरे चरण के कार्य को 15 महीने का विस्तार दिया गया है। अब इस योजना को जून 2024 तक पूरा किया जाएगा।
- राज्य सरकार ने कुशहा तबाही के बाद कोसी के पुनर्निर्माण की योजना बनाई है। इसके तहत कोसी क्षेत्र और यहाँ के लोगों को त्रासदी से बाहर निकालने और विकास के लिये विश्व बैंक ने 67% और बिहार सरकार 33% की फंडिंग की है।
- इस योजना के पहले चरण के अंतर्गत विश्व बैंक की मदद से 15 सितंबर, 2010 को बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना की शुरूआत हुई, जिसके तहत सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के 21 प्रखंडों में 31 दिसंबर, 2018 को विकास कार्य समाप्त हो चुका है।
- विदित है कि 18 अगस्त, 2008 को नेपाल के कुसहा गाँव के समीप लगभग दो किलोमीटर की लंबाई में कोसी नदी की धारा बदल लेने के बाद कोसी बाँध के बह जाने से नेपाल के 34 गाँव समेत पूर्वोत्तर बिहार के 441 गाँवों की बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में आई थी। सरकारी आँकड़ों के अनुसार इस बाढ़ से सहरसा ज़िले में 41, मधेपुरा में 272 और सुपौल ज़िले में 213 लोगों की मौत हुई थी।
- कोसी बेसिन विकास परियोजना के दूसरे चरण का काम इस समय मात्र 72 फीसदी ही पूरी हो पाया है, बाकी बचे शेष 28 फीसदी काम का तीन महीने में पूरा होने की संभावना नहीं के बराबर है। इसलिये इस योजना के विस्तार का निर्णय लिया गया है।

नोट :

शिक्षा के क्षेत्र में देश के टॉप पाँच ज़िलों में शेखपुरा पहले और पूर्णिया दूसरे स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

13 अप्रैल, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी ज़िलों की डेल्टा रेटिंग में शिक्षा सेगमेंट में देश के टॉप पाँच ज़िलों में बिहार का शेखपुरा ज़िला पहले और पूर्णिया ज़िला दूसरे स्थान पर रहा।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि शिक्षा के क्षेत्र में देश के टॉप पाँच आकांक्षी ज़िलों की लिस्ट में बिहार और झारखंड के ज़िलों के नाम रहे हैं। झारखंड के गिरीडीह, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम क्रमश: तीसरे, चौथे और पाँचवें नंबर पर रहे।
- नीति आयोग द्वारा जारी की जाने वाली आकांक्षी ज़िलों की डेल्टा रेटिंग के शिक्षा सेगमेंट में मुख्य रूप से पढ़ाई, लाइब्रेरी, स्कूलों की संरचना, छात्रों के लिये उपलब्ध सुविधा आदि पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में स्कूलों में उपलब्ध पेयजल और टॉइलेट की सुविधा पर भी ध्यान दिया जाता है।
- हालाँकि, नीति आयोग द्वारा फरवरी 2023 की जारी चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग के ओवर ऑल सेगमेंट में बिहार का एक भी ज़िला नहीं है।
- वहीं, स्वास्थ्य और पोषण के टॉप पाँच ज़िलों में झारखंड के साहिबगंज पहले और बोकारो-दूसरे स्थान पर है।
- देश के अल्पविकसित 112 ज़िलों में वर्ष 2018 से चल रहे आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम में बिहार के 13 ज़िले हैं। इन ज़िलों के बीच बेहतर काम हो, इसके लिये प्रति महीना इन ज़िलों के विकास के निर्धारित पैमाने पर रैंकिंग की जाती है।
- विदित है कि केंद्र सरकार देश के आकांक्षी ज़िलों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा व वित्तीय स्थिति और आधारभूत अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों को विकसित करने पर विशेष राशि देती है।

बिहार में जाति गणना के दूसरे चरण का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

15 अप्रैल, 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 2 करोड़ 59 लाख परिवारों की जाति आधारित गणना की शुरूआत बख्तियारपुर स्थित अपने पुस्तैनी घर जाकर परिवार के सभी आँकड़े दर्ज करवाकर की।

प्रमुख बिंदु

- जाति गणना का यह दूसरा चरण 15 मई, 2023 तक चलेगा। इस गणना के लिये पूरे राज्य में 5 लाख 19 हज़ार कर्मचारी लगाए गए हैं।
- इस चरण में राज्य के समस्त परिवारों से 17 प्रकार की जानकारी मांगी जा रही है। प्रत्येक जानकारी के लिये एक कोड निश्चित किया गया है, जिसे एप पर दर्ज किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है बिहार में जातीय गणना का प्रथम चरण 7 से 22 जनवरी के मध्य चला, इसमें लोगों के मकानों की जानकारी एकत्रित की गई।
- गौरतलब है कि बिहार में कई राजनीतिक दलों द्वारा लंबे समय से जातीय गणना की मांग की जा रही थी। जिसके चलते 18 फरवरी, 2019 और फिर 27 फरवरी, 2020 को बिहार विधानसभा और विधान परिषद् में जातीय गणना कराने से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे समस्त दलों ने समर्थन दिया था।
- भारत सरकार ने भी वर्ष 2011 की जनगणना में जातीय गणना की थी लेकिन आँकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया था।
- बिहार की इस जातीय गणना पूरी होने के बाद इसकी रिपोर्ट राज्य की विधानसभा और विधान परिषद् में पेश की जाएगी और फिर इसे सार्वजनिक किया जाएगा।
- इस जातीय गणना से राज्य में जातियों की संख्या, उनकी आर्थिक स्थिति का पता चल सकेगा जिससे सरकार को आरक्षण का प्रावधान करने एवं विभिन्न योजनाओं के सही क्रियान्वयन में मदद मिल सकेगी।

नोट :

बिहार की अंजनी ने भाला फेंक में जीता स्वर्ण

चर्चा में क्यों ?

15 अप्रैल, 2023 को बिहार के जमुई की अंजनी कुमारी ने बंगलुरू में आयोजित इंडिया ग्रांड प्रीक्स-4 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

प्रमुख बिंदु

- अंजनी ने सीनियर महिला वर्ग में 47.03 मीटर दूर भाला फेंककर तमिलनाडु की हेमा-मालिनी नीलाकंडा (46.27मी.), राजस्थान की उमा चौधरी (45.73मी.) और असम की रुनजुन पेगु (43.62मी.) को हराकर सफलता हासिल की।
- इस अवसर पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि अंजनी का चयन एनआईएस पटियाला स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिये किया गया है।
- अंजनी कुमारी यहाँ 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 2023 तक एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और वर्ल्ड एथेलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के लिये तैयारी करेगी।
- उल्लेखनीय है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) द्वारा कुल चार इंडियन ग्रां प्री एथलेटिक्स इवेंट आयोजित किये गए। इसके प्रथम चरण का शुभारंभ 20 मार्च, 2023 से केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था।
- इंडियन ग्रां प्री का दूसरे चरण 27 मार्च को तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया, जबकि तीसरा और चौथा चरण क्रमश: 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को बंगलुरु, कर्नाटक में हुआ।

दरभंगा में बनेगा बिहार का दूसरा एम्स, कैबिनेट ने तीन अरब से अधिक राशि की प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों ?

18 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिये तीन अरब से अधिक राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में जानकारी देते हुए जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि दरभंगा एम्स के लिये आवंटित भूमि के समतलीकरण एवं विकास पर बिहार सरकार 309 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी।
- राज्य मंत्रिमंडल ने दरभंगा एम्स की स्थापना के उद्देश्य से बहादुरपुर अंचल अंतर्गत शोभन-एकमी बाईपास के निकट मौजा बलिया में कुल 189.17 एकड़ भूमि में मिटी भराई कर उसके समतलीकरण के लिये उक्त राशि की स्वीकृति दी है।
- विदित है कि दरभंगा में बनने वाला यह एम्स बिहार का दूसरा एम्स होगा, पहला एम्स पटना में है।
- गौरतलब है कि मार्च 2023 के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिये शोभन-एकमी बाईपास के निकट भूमि आवंटित करने को मंजूरी दी गई थी।
- इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने मुजफ्फरपुर और भागलपुर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के तहत DNA रिसर्च सेंटर खोलने का निर्णय लिया है।

बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को मिलेगा जीआई टैग

चर्चा में क्यों ?

23 अप्रैल, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के प्रसिद्ध मिठाई खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को जीआई टैग देने संबंधी आवेदन को प्रारंभिक जाँच के बाद स्वीकार कर लिया गया है। सक्षम प्राधिकार इस दिशा में अब आगे की कार्रवाई करेगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार भोजपुर के उदवंतनगर का खुरमा, गया का तिलकुट, सीतामढ़ी की बालूशाही, हाजीपुर का प्रसिद्ध चीनिया केला, नालंदा की मशहूर बावन बूटी कला और गया की पत्थरकटी कला को जीआई टैग देने की मांग मंज़ूर हो गई है।
- जीआई टैग किसी उत्पाद की उत्पत्ति को मुख्य रूप से उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिये दिया जाता है।
- नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक सुनील कुमार ने कहा कि भोजपुर का 'खुरमा' और गुड़-तिल से बनाया जाना वाला गया का तिलकुट न केवल देश, बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद किये जाते हैं। वहीं, सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर की मिठाई बालूशाही की भी देशभर में काफी डिमांड है।
- सुनील कुमार ने बताया कि बिहार के इन प्रसिद्ध पकवानों और उत्पादों के लिये जीआई टैग की मांग संबंधी आवेदन दाखिल करने में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने उत्पादक संघों की सहायता की है। इसके लिये विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है।
- नाबार्ड जीआई पंजीकरण की प्रक्रिया के अलावा बाज़ार में इन उत्पादों की ब्रांडिंग, प्रचार और बाज़ार संपर्क दिलाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है।
- नाबार्ड ने उम्मीद जतायी है कि इन पकवानों और उत्पादों को जीआई टैग मिलने से इनसे जुड़े किसानों, उत्पादकों और कलाकारों को अधिक कमाई करने में मदद मिलेगी।
- गौरतलब है कि हाल ही में राज्य के प्रसिद्ध मर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया था, जो अपनी सुगंध और स्वाद के लिये जाना जाता है। भागलपुर के जरदालु आम और कतरनी धान, नवादा का मगही पान और मुज़फ्फरपुर की शाही लीची को पहले ही जीआई टैग मिल चुका है।

बिहार में 454 किलोमीटर फोर लेन को केंद्र की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

- 25 अप्रैल, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने बिहार में 454 किलोमीटर के चार नये फोरलेन को मंज़ूरी दे दी है। ये फोरलेन विभिन्न इलाकों से होकर गुज़रेंगे।

प्रमुख बिंदु

- भारत नेपाल सीमा से सटे वाल्मीकिनगर से झारखंड सीमा के हरिहरगंज तक बिहार में 454 किलोमीटर का एक नया फोरलेन होगा। ये फोरलेन पटना के नौबतपुर से हरिहरगंज तक 143 किलोमीटर नेशनल हाईवे 98 को केंद्र ने फोरलेन में कनवर्ट करने की मंज़ूरी दी है।
- विदित है कि अभी नेशनल हाईवे 98 की चौड़ाई कुल दो लेन की है। इस हाइवे पर गाड़ियों का दबाव बहुत ज्यादा है। सोन नदी के पूर्वी छोर से बिल्कुल पास होकर गुज़रता ये नेशनल हाइवे बिक्रम-अरवल-औरंगाबाद और अंबा होते हुए हरिहरगंज तक जाता है।
- झारखंड राज्य के पश्चिमी छोर के गढ़वा - डालटेनगंज और छत्तीसगढ़ तक जाने वालों के लिये ये एक बिल्कुल सुगम रास्ता है, जिसकी वजह से इस हाईवे पर गाड़ियों का दबाव लगातार बना रहता है।
- जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने अब इस नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाने के लिये डीपीआर तैयारी करने की मंज़ूरी दी है। साथ ही इसके लिये एक करोड़ 38 लाख की राशि भी स्वीकृत कर ली गई है।
- पटना से बेतिया तक पाँच हज़ार छह सौ करोड़ की लागत से 195 किलोमीटर लंबा फोरलेन हाईवे का निर्माण शुरू है। ये नेशनल हाईवे बुद्ध सर्किट का मुख्य हिस्सा है। इसी हाईवे के किनारे केसरिया का बौद्ध स्तूप भी है।
- जेपी सेतु के बगल में पटना के दीघा से सोनपुर के बीच दो हज़ार 636 करोड़ की लागत से सवा तीन साल में बनने वाले 6 लेन ब्रिज का टेंडर हो चुका है। इसके अलावा सोनपुर मानिकपुर में गंडक नदी पर सारण के कोन्हारा घाट से वैशाली के जलालपुर के बीच पुल बनाने के लिये 868 करोड़ का टेंडर हो चुका है। जिन हिस्सों का टेंडर होना बाकी है, उसमें मानिकपुर से साहेबगंज, साहेबगंज से अरेराज, अरेराज से बेतिया शामिल हैं। इन तीनों हिस्सों की कुल लागत दो हज़ार 159 करोड़ होने वाली है।
- इस नये फोरलेन के बनते ही वाल्मीकिनगर से हरिहरगंज तक का सफर 11 घंटे से घटकर मात्र 6 घंटे का रह जाएगा। इसके अलावा झारखंड के पश्चिमी इलाके पलामू, चपतरा से नेपाल पूरी तरह सीधी तौर पर जुड़ जाएगा। इससे ढुलाई में काफी सुविधा होगी। इसका लाभ बिहार और झारखंड के व्यापारियों को होगा।

नोट :

- ये लेन आगे वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे से भी सीधे जुड़ जाएगी। जिससे व्यापारियों को माल ले जाने और ले आने में सुविधा होगी। इसके अलावा सिलीगुड़ी और असम की तरफ जाना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा।
- सोनपुर से अरेराज तक गंडक नदी के पश्चिमी किनारे की तरफ भी फोर लेन का निर्माण होगा, जिससे सारण कमिश्नरी के दो ज़िले सारण और गोपालगंज के दियारा इलाके में आवागमन सुगम होगा।

आईआईटी पटना और रॉइनेट सोल्यूशन के बीच हुआ एमओयू

चर्चा में क्यों ?

27 अप्रैल, 2023 को आईआईटी पटना ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर रॉइनेट सोल्यूशन के साथ एमओयू साइन किया। इसके तहत आईआईटी, पटना जूम, वाट्सएप व गूगल पे जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म विकसित करेगा।

प्रमुख बिंदु

- रॉइनेट सोल्यूशन के प्रबंध निदेशक समीर माथुर और आईआईटी पटना के निदेशक प्रो. टी.एन. सिंह ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
- निदेशक प्रो. टी.एन. सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य अत्याधुनिक समाधान विकसित करना तथा शोध की दिशा में बेहतर काम करना है।
- रॉइनेट सोल्यूशन और आईआईटी पटना संयुक्त रूप से अगले तीन वर्षों में डिजिटल पेमेंट, धन प्रबंधन, सीमा पार भुगतान, सुरक्षित ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाएँ शुरू करेंगे, जिनमें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स आदि शामिल हैं।
- आईआईटी पटना पटना जूम, वाट्सएप व गूगल-पे जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। इसका नाम फॉरेक्स प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। इसमें आईआईटी, पटना एकेडमिक स्तर पर और रॉइनेट सोल्यूशन बाज़ार पर काम करेगी।
- रॉइनेट सोल्यूशन के निदेशक डॉ. लिम चोन-फंग ने कहा कि आईआईटी, पटना को हम सभी प्रकार से सहयोग करेंगे, एकेडमिक सहयोग आईआईटी का रहेगा। आईआईटी पटना अपने शोध और अकादमिक उत्कृष्टता के लिये जाना जाता है। यह साझेदारी हमें आईआईटी पटना की विशेषज्ञता का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी।
- विदित है कि आईआईटी पटना ने पिछले तीन दिनों में रेलटेल, एप्लाइड मैटेरियल्स इंडिया और रॉइनेट के साथ तीन अलग-अलग एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं। जिन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए हैं, वे सब समाज को नये आविष्कार और विकास की ओर ले जाएंगे।

नोट :